

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. - 5617/2017 Shri Yogesh Khare, Sakin Khare Building, Gandhigani, Murwara, Katni, MP – 483501. Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 1.870 Ha.. (25,266 ton per annum) (Khasra no. 503 New 867, 955) at Village- Rupaund, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP). EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)

This is case of Limestone & Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site is located at (Khasra no. 503 New 867, 955) at Village- Rupaund, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 1.870 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 328वीं दिनांक 08/09/2018 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी, जिसकी वैधता सितम्बर, 21 तक थी, जिसे सिया के पत्र क्रमांक 2334 दिनांक 18/10/21 द्वारा टॉर वैधता की अवधि 21/09/22 तक बढ़ाई गई । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई. ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के बीच से कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूँकि खनन कार्य बंद है इसलिए ग्रामीणों द्वारा आने-जाने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रोड़ के दोनों ओर 50 मीटर का सेट-बैक छोड़ते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप के साथ प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया गया है । इसी प्रकार दक्षिण दिशा में

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

50 मीटर पर उद्योग स्थित है, जिसके संरक्षण के बारे में बताया कि इस ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा तथा 04 मीटर ऊँची विंड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है । समिति ने पाया कि विंड ब्रेकिंग वॉल का खर्चा ई.एम.पी. शामिल नहीं है, अतः पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत करें । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक सीमेंट उद्योग है तथा हमारी खदान से उत्पन्न होने वाला लाईम स्टोन इन्हीं को दिया जाना प्रस्तावित है । आवंटित खनन क्षेत्र के बीच में 01 केशर स्थापित है तथा खनन क्षेत्र बीच से खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि यह पुरानी खदान है जिसमें वर्ष 2004 से 2012 तक कोई उत्पादन नहीं हुआ तथा वर्ष 1994 से 2004 तक तथा वर्ष 2012 से 2014 तक खनन कार्य किया गया है तथा कुल 19,794.80 टन लाईम स्टोन का उत्पादन किया गया है। समिति ने पाया कि इस खदान को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 13/01/16 के द्वारा सम्मति प्रदान की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 11/09/18 तक थी । समिति ने यह पाया कि पर्यावरणीय सलाहकार के कथनानुसार यदि वर्ष 2012 से 2014 तक खनन कार्य किया गया है तो फिर वर्ष 2016 में सम्मति क्यों प्राप्त की गई । इस दौरान ऑन लाईन उपस्थित परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2016 में भी खनन कार्य किया गया है । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताई गई जानकारी एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी में भिन्नता परिलक्षित हुई तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है । तत्संदर्भ में समिति द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार को ताकीद किया गया कि भविष्य में प्रकरण के सभी पहलुओं का सही अध्ययन/परियोजना प्रस्तावक से चर्चा एवं प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति एवं सारगर्भित जानकारी के साथ समिति के समक्ष उपस्थित हो अन्यथा सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जावेगी । उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2014 के बाद भी खनन कार्य किया गया है । अतः इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त की जाये कि क्या वर्ष 2014 के पश्चात् खनन कार्य किया गया है तथा इस खदान द्वारा वर्ष 2012 से आज दिनांक तक प्रतिवर्ष कितनी रॉयल्टी जमा की गई है। प्रकरण के गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य तो किया गया है किंतु सम्मति की शर्त अनुसार कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया, जिसके संदर्भ में ऑनलाईन उपस्थित परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे ने बताया कि उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया था किंतु खदान के अकार्यशील होने के कारण वे जीवित नहीं रह पाये तथा अभी उनके पास उनसे संबंधित प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा वे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त निर्देशानुसार वृक्षारोपण करेंगे । समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक चूंकि पूर्व में खनन कार्य कर चुका है, अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति अनुसार वृक्षारोपण कर, उनसे संबंधित फोटोग्राफ प्रस्तुत करें । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गाँव की पानी की समस्या, धूल की समस्या तथा वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

- ✓ खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर स्थापित उद्योग के संरक्षण हेतु 04 मीटर ऊँची विंड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण का खर्चा ई.एम.पी. में शामिल करते हुए पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत करें ।
- ✓ जिला खनिज अधिकारी से प्रमाणिक जानकारी कि क्या वर्ष 2014 के पश्चात् भी इस खदान में खनन कार्य किया गया है तथा इस खदान द्वारा वर्ष 2012 से आज दिनांक तक जमा की गई रॉयल्टी की वर्षवार जानकारी ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक चूँकि पूर्व में खनन कार्य कर चुके हैं, अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति अनुसार वृक्षारोपण कर, उनसे संबंधित फोटोग्राफ प्रस्तुत करें ।

2. Case No 8670/2021 M/s Mahadev Stone Crusher Industries, Shri Abhay Singh, Partner, 201, Tansen Nagar, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.332 ha. (23726 cum per annum) (Khasra No. 05), Village - Chirpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) M/s. Forest Environment and Climate Change Management Consultancy (FECCM), Pvt. Ltd. Bhopal, MP.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05), Village - Chirpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.332 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभय सिंह चौधरी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सैयद तनवीर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पूर्वी दिशा में 15 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 100 मीटर दूरी पर रोड़ तथा उत्तर दिशा में 245 मीटर की दूरी पर आबदी है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान विद्यालय में पुताई, सोलर पैनल की स्थापना व रोड़ की मरम्मत, वृक्षारोपण तथा मेडिकल चेकअप कैम्प आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/07/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 23,726 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु 08.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.33 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख :-

क्र.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
1	गॉव चिरपुरा के प्राथमरी स्कूल में व्हाइट वॉश, 02 सोलर लाईट तथा स्कूल की सड़क की मरम्मत।	1,00,000
2	गॉव वालों की आवश्यकतानुसार 300 फलदार पौधों का वितरण।	15,000
3.	गॉव वालों की स्वास्थ्य जाँच कैम्प।	25,000
कुल		1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा:

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, कदम, नीम, शीशम, करंज, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। ट्री-गार्ड के साथ।	400
3	स्कूल प्रांगण में	नीम, पीपल, पलास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	250
4	ग्राम पंचायत भवन चिरपुरा और लटेरा में पौधा रोपड़ एवं ग्राम वासियों को वितरण	आम मुनगा कटहल नीबू एवं नीम	550
कुल			1600

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

3. Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Environment Consultant : Globus Environment Engineering Service, Lucknow.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 29/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.105 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। इसी प्रकार खदान के पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर रोड़ है। प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खुदी होने के कारण टॉर वॉयलेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

4. Case No 9259/2022 Smt. Binu Solanki, Owner House No. 97, Ward No. 07, Rawla Gali, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 385/2/2) Village - Jiwangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 385/2/2) Village - Jiwangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 866 दिनांक 10/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 190 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वर्ष 2013 से खुदा है, तत्संबंध में विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 190 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वर्ष 2013 से खुदा है, तत्संबंध में विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. Case No 9260/2022 General Manager, Madhya Pradesh State Mining Corporation, Block No. 1(A), 2nd Floor, Jail Road, Paryavas Bhawan Arera Hills, Dist. Bhopal, MP - 462011, Prior Environment Clearance for Bauxite Mine in an area of 21.0 ha. (OB - 2500 cum per annum, Bauxite - 99643 Tonne per annum, Laterite - 21144 Tonne per annum) (Khasra No. 03, 07) Village - Tamar & Kirkiran, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Bauxite Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 03, 07) Village - Tamar & Kirkiran, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna, (MP) 21.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खनिज बाक्साइट (लीज एरिया 21.00 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 85 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर जलाशय है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 85 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर जलाशय है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. चूक खनन क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है, अतः सरफेस रनऑन मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
5. आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी.एफ. ओ) का प्रमाण-पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट तथा ईको सर्विसेस स्टण्ड्री (पारिस्थितिक तंत्र सेवा) की जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज निस्तार की भूमि है, अतः इसके प्रतिपूर्ति उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

6. Case No 9255/2022 Shri Rajat Choudhary, Lessee, 424, Village - Hridaypur, Damoh Khas, Dist. Damoh, MP - 470661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.589 ha. (16500 cum per annum) (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandhpur, Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandhpur, Tehsil -

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

Buxwaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.589 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

7. Case No 9256/2022 Smt. Meena Patel, Plot no. 18 Kashoda Nagar, Madhotal, Baldevbag, Dist. Jabalpur, MP - 482002, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.20 ha. (11400 cum per annum) (Khasra No. 184) Village - Aithakhera, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur, MP

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 184) Village - Aithakhera, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur, (MP) 2.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आर. के. चौबे उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807 दिनांक 15/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.46 हे. होता है।

समिति ने पाया कि पूर्व में यह प्रकरण क्रमांक 8768/2021 के द्वारा सेक में प्राप्त हुआ था जिसके अनुशंसा सेक की 538वीं बैठक दिनांक 06/01/22 के माध्यम से की गई थी किंतु सिया ने उनकी 702वीं बैठक दिनांक 28/01/22 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया, जिसके पालन में परियोजना प्रस्तावक ने नवीन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण की विवेचना करने पर ज्ञात हुआ कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807 दिनांक 15/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.46 हे. होता है किंतु सिया द्वारा प्रकरण ऑनलाईन बी-2 श्रेणी में स्वीकार कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी ने 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

की जानकारी में सहायक मानचित्रकार के पत्र दिनांक 30/03/22 के अनुसार 02 अन्य खदानें पत्थर गिट्टी की हैं, जिनका कुल एरिया 15.160 हे. है तथा प्रश्नाधीन खदान (2.20 हे.) मुरुम की होने के कारण नॉन होमोजिनियस है, इसलिए यह प्रकरण बी-2 श्रेणी में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री आर. के. चौबे को समिति ने निर्देशित किया कि वे यह बतायें कि किस प्रकार स्टोन एवं मुरुम नॉन होमोजिनियस है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 75 मीटर पर आबादी है, अतः खनन क्षेत्र में 25 मीटर का सेट-बैक (खनिज मुरुम होने के कारण नॉन ब्लास्टिंग) छोड़ा जाना होगा जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व से ही 25 मीटर का सेट-बैक आबादी के कारण छोड़ा गया है तथा प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया गया है। इसी प्रकार खनन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा में 280 मीटर पक्का रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार का औचित्य कि किस प्रकार स्टोन एवं मुरुम नॉन होमोजिनियस है।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/07/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 11,400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.25 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.75 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम ऐंटाखेड़ा में 05 वर्ष तक ऑगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण / वर्ष रु. 20,000 / -	1,00,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

1	बैरियर जोन में	नीम, (नीम सीड सोइंग के साथ) खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ट्री-गार्ड के साथ	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
4	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा में वितरण	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
5	ग्राम ऐंठाखेड़ा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल वृक्षारोपण	2500

8. Case No 9257/2022 Shri Ashish Tiwari S/o Shri Balkrishna Tiwari, Niwasi - Navalpur, Tehsil - Sohagpur, Dist. Shahdol, MP - 461771 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (25171 cum per annum) (Khasra No. 1728/1) Village - Dhangawan, Tehsil - Gohparu, Dist. Shahdol, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed (Khasra No. 1728/1) Village - Dhangawan, Tehsil - Gohparu, Dist. Shahdol, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1697 दिनांक 12/02/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 200 मीटर पर नदी है तथा सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं, जिनकी इवेंट्री प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक यह भी नहीं बता सके कि लीज क्षेत्र में कितने पेड़ हैं, किस प्रजाति के हैं तथा उनमें से खनन के

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

दौरान कितने पेड़ काटे जाने हैं । अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वे ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई, गर्थ सहित ड्रोन विडियोग्राफी के साथ प्रस्तुत करें।

9. Case No 9159/2022 M/s Vijay and Company, Partner Shri Anshuman Rai, Rai Bhawan, Katni Road, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, MP - 485771 Prior Environment Clearance for Stone / M-Sand Quarry in an area of 3.610 ha. (85500 Tonne per annum) (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP)

This is case of Stone / M-Sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 3.610 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2896 दिनांक 22/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 65 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी है, कच्चा रास्ता नहीं है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सैंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लॉन page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-14.6 में Ground Water Table From 0.97 To 16.9, (डिस्ट्रिक ग्राउण्ड वाटर इंफारमेशन बुकलेट अनुसार डेटा वर्ष 2012 का है), अतः परियोजना प्रस्तावक वर्तमान Ground Water Table डेटा उपलब्ध करायें ।
- ✓ एम-सैंड प्लांट की लोकेशन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप तथा एम-सैंड प्लांट का ले-आउट ।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- ✓ एम-सेंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी., वृक्षारोपण एवं सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 02/06/22 को अपलोड किया गया। प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है क्योंकि रिवाइज फार्म-2 में जानकारी चाही गई थी किंतु परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-2 के स्थान पर पी.एफ.आर. प्रस्तुत की है। अतः परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी पुनः प्राप्त की जाना प्रस्तावित है :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सेंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लान page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ एम-सेंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 27/06/22 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि उनके द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सेटलिंग टैंक एवं स्जल ड्राइंग बेड का प्रावधान किया गया है तथा पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुतीकरण में संलग्न है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन एवं एम-सेंड - 85,500 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.84 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
• ग्राम तमोरिया के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	50,000/-
• ग्राम तमोरिया के ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा।	20,000/-
योग	

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4340 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, सेमल, जंगल जलेबी, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, देसी आम, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3	तमोरिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, मुनगा इत्यादि।	1700
4.	शासकीय विद्यालय तमोरिया में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	40
कुल वृक्षारोपण			4340

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला - पन्ना (म.प्र.).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 864 दिनांक 28/06/22 के माध्यम से पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-पन्ना, म.प्र. के पत्र क्र०. 733 दिनांक 15/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में ऑनलाईन जमा कराई गई। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति के सदस्यों को दिनांक 28/06/22 को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 584 बैठक दिनांक 05/07/2022 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 584 बैठक दिनांक 05/07/2022 में पन्ना जिले की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग की ओर से श्री रवि कुमार पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये। चर्चा के दौरान समिति ने खनिज अधिकारी को बताया कि प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में वर्णित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है, जैसे :-

1. तालिका क्र०. 3 (पेज न०. 8-14) जो कि रेत खनन से संबंधित है यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्वीकृत खदानों की वैधता की अवधि नहीं दी गई हैं।
2. तालिका क्र०. 4 फ्लेग स्टोन (पेज न०. 15-30), तालिका क्र०. 5 स्टोन गिट्टी (पेज न०. 31-38) एवं तालिका क्र०. 6 (पेज न०. 38) में भी प्रदाय की गयी जानकारी पूर्ण नहीं है। संबंधित अधिसूचना में उपरोक्त जानकारी 16 कॉलमों में समाहित की गयी है। अतएव तदनुसार गौण

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

खनिजों की जानकारी का उन्नयन करें।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जितने भी नक्शे संलग्न किये गये हैं, उन्हें रंगीन प्रिंट में लगायें जिससे की लीजेण्ड में दी गई जानकारी को नक्शे में दर्शाये गये फीचर्स से सामंजस्य हो सके। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेण्ड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके। यदि ए-4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए-3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
4. पेज न0. 53 में दर्शायी गयी पाई डायग्राम की जानकारी भी कलर्ड प्रिंट करके लगाये।
5. तालिका क्र0. 15 (पेज न0. 63) में नदियों के कैचमेंट की जो जानकारी दी गयी है उसके दुबारा पुनरिक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।
6. बिन्दु क्र0. 19 (पेज -67) में ESZ में अधिसूचित केन घड़ियाल अभ्यारण की जानकारी का भी समावेश किया जाये। चूंकि पारिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का नम्बर, दिनांक एवं विस्तार और सीमाओं का समावेश होना अपरिहार्य है।
7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक— 20, 21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता की गणना, स्वीकृत के परिप्रेक्ष्य में की जाना चाहिए। यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है।
8. बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
9. तालिका क्रमांक-25 में जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि जिले में प्रतिशत निष्काषित क्षेत्र की जानकारी नहीं दी गई है।
10. तालिका क्रमांक-27 एवं 28 में जानकारी खदानवार लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में वर्णित प्रपत्र के अनुरूप प्रस्तुत की जाये।
11. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटাইज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेरेवल - सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
12. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू-वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिले में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जुलाई 2022

13. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशील क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
14. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री रवि कुमार पटेल, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

584वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained